झारखण्ड की योजनाए -1

योजना – भारत एक कल्याणकारी राज्य है । भारत के संविधान मे भाग 4 मे नीति निदेशक तत्व की चर्चा है और इसके प्रावधान कल्यानकारी राज्य की स्थापना की बात करता है ।

- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार समय–समय पर देश के गरीबों , वंचितो , किसानो , मजदूरों , वृद्धो , दिव्यांगो , श्रमिकों व अन्य लोगो के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती है । जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है ।

❖ झारखंड राज्य निर्माण के बाद की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं

- झारखंड एक आदिवासी बहूल गरीब राज्य है और इसलिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं इस राज्य की बड़ी जरूरत है ।
- अब तक बनी सभी सरकारों ने राज्य के गरिबों, वंचितो , किसानो , महिलाओं आदि के लिए योजनाएं बनाई है जिसमें से कई योजनांए अभी भी चल रही है ।

- इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कर का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना होता है और वह करती भी है । मगर फिर भी इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता ।

झारखंड सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं

❖ वर्ष 2019 मे हेमन्त सोरेन सरकार बनने के पश्चात शुरू की गई योजनांए

1. झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना

- इस योजना के तहत एक परिवार के एक सदस्य के अधिकतम 50,000 रू. तक के कृषि ऋण माफ करने की योजना है । यह ऋण 31 मार्च 2020 या इसके पूर्व के होने चाहिए ।
- इस योजना से राज्य के करीब नौ लाख लोगों के लाभ होगा ।

2. मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति योजना

- इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसुचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को चयनित कर के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दन आयरलैंड के चयनित संस्थानों/विश्व विद्यालयों अथवा संस्थानों मे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति दी जाएगी ।
- इस योजना के तहत 22 विषयों में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध है।
- ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखड देश का प्रथम राज्य है ।

योजना के लाभार्थी कौन होगें?

1.आवेदक माता–पिता की संपूर्ण परिवारिक आय 12 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

2. आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए।

3. आवेदक को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।

➢ इस योजना के तहत शामिल यूनिवर्सिटी निम्नलिखित है –

1.यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन

2. यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज

3. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी

4. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर

5. यूनिवर्सिटी ऑफ विस्टल

6. यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक

7. यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग

8. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास

9. इंपीरियल कॉजेज लंदन

10. लंदन स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान

11. यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग

12. क्रिंग्स कॉलेज लंदन

13. एस ओएएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन।

3. झारखंड राज्य फसल राहत योजना

- इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति होने पर राज्य सरकार किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देगी । इसके लिए 100 करोड़ का बजट है ।

4. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना

- इसके तहत परिवार की महिला मुखिया के नाम पर हरा राशन कार्ड दिया जाएगा और 1रू प्रति किलो की दर पर पांच किलोग्राम चावल दिया जाएगा ।
- राज्य के 15 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा ।

5. सर्वजन पेंशन योजना (यूनिवर्सल पेंशन स्कीम)

- इसकी शुरूआत 15 नवंबर 2021 को हुई।
- इस योजना के तहत सभी 60 वर्ष या उससे अधिक वृद्धों को जोड़कर उनके कल्याण का फैसला सरकार ने किया है ।
- इसमें विधवा , एकल परित्यक्त महिलाएं भी लाभान्वित होगी।
- यह मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का बदला हुआ रूप है जिसे सार्वभौमिक किया गया है ।

- नई योजना के तहत 100 फीसदी वृद्धों ,दिव्यांगो, विधवा एवं परित्यक्त महिला को प्रतिमाह 1000 रू. पेंशन के रूप मे बैंक खाते मे उपलब्ध कराई जाएगी ।

6. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

- राज्य मे दुध , मांस , अंडा उत्पादन मे वृद्धि लाने , ग्रामीण क्षेत्रों मे पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन और अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन करने के उदेश्य से इस योजना की शुरूआत किया गया है ।

7. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

- इस योजना के तहत युवाओं एंव बेरोजगारो को स्वरोजगार के लिए आसान शर्तो पर ऋण देने की शुरूआत की गई है ।

8. झारसेवा अभियान

- सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र , विवाह पंजीकरण आदि सेवाओं को निर्धारित समय मे उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान की शुरूआत हुई है ।
- सरकार इसमे जिरो पेडेंसी सुनिश्चित करेगी

9. सोना सोबरन धोती साड़ी योजना (200 करोड़)

- 16 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित हुई इस योजना के तहत राज्य के लगभग 57 लाख बीपीएल परिवारों को 10रू प्रति पीस के हिसाब से साड़ी एवं धोती दिए जाएगें ।
- साड़ी व धोती या लुंगी का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से साल मे दो बार कराई जाएगी ।
- इसका लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड

10. दीदी बाड़ी योजना

- झारखंड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण यूक्त भोजन उपलब्ध करवाने तथा बेरोजगारी जैसी समस्या का दूर करने के लिए मनरेगा के तहत दीदी–बाड़ी योजना शुरू की गई है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से किया जा रहा है ।

योजना के दो प्रमुख लक्ष्य

- कोविड–19 के चलते बेरोजगार हुए लोगों को इससे जोड़कर उन्हे प्रशिक्षित कर के रोजगार उपलब्ध करवाना तथा उनकी आमदनी बढाना
- बच्चों व महिलओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा कर कुपोषण जैसी समस्या को खत्म करना ।

11. बिरसा हरित ग्राम योजना

- इस योजना का मुख्य उदेश्य श्रमिको व प्रवासी मजदूरो को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना है ।
- यह योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है ।
- इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को सौ–सौ फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे जिससे पांच करोड़ पौधा रोपन होगा ।

- योजना के अंतर्गत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होग । तीन साल बाद 50000 रू वार्षिक आमदनी भी होगी ।
- पौधों को अगले 5 वर्ष तक सुरक्षित रखने के लिए सरकार सहयोग करेगी । प्रखंड व जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी।

12. नीलाम्बर–पीताम्बर जल समृद्धि योजना (4 मई 2020)

- इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता मे पांच करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य है ।
- इस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा तथा इसके तहत 10 करोड़ मानव दिवसका सृजन होगा ।
- इसके तहत पलामू, लातेहार तथा गढवा के सुखे की व्यवस्था मे सुधार करना है ।

13. पोटो हो खेल विकास योजना (4 मई 2020)

- इस योजना के तहत राज्य भर के सभी पंचायतो सहित 5000 खेल मैदानों के निर्माण का लक्ष्य है तथा युवक व युवतियों के लिए खेल सामाग्री की व्यवस्था की जाएगी ।
- इस योजना के तहत प्रखंड व जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना है ।

14. गुरू जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

- इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, पी.एच डी एंव शोध करने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 15 लाख तक ऋण दिया जाएगा।
- कोर्स पुरा होने के एक साल बाद से ई एम आई चुकाना होगा।

15. मुख्यमंत्री सारथी योजना

- रोजगार के लिए ट्रेंनिग के उदेश्य से शुरू की गई योजना।
- प्रखंड स्तर पर रोजगार के लिए ट्रेंनिग के उदेश्य से शुरू की गई है मुख्यमंत्री सारथी योजना।
- गैर आवासीय ट्रेनिंग के लिए 1000रू यात्रा भत्ता
- यदि ट्रेनिंग के तीन माह तक रोजगार नही मिला तो एक वर्ष तक युवाओ को 1000 तथा युवतियों एवं दिव्यांगो को 1500रू प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा।

16. एकलव्य प्रशिक्षण योजना

- इस योजना के तहत युवाओं को सिविल सेवा, बैंक , एस एस सी व रेलवे परीक्षा की तैयार कराई जाएगी।
- पहले साल 27000 छात्रों को कोंचिग मिलेगी।
- इसमें वैसे यूवा शामिल होंगे जिनके अभिभावक आयकर दाता ना हो।
- कोंचिग के बाद हर महिने 2500 रू की छात्रवृति मिलेगी।

17. शिक्षा प्रोत्साहन योजना

- 10वीं पास विद्यार्थियों के इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लेट, होटल मैनेजमेंट व सी.ए परीक्षा की तैयारी कराने के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की गई है।
- इसमें पहले वर्ष 8000 छात्रो को जोड़ने की योजना है।
- इन्हे हर माह 2500 रू छात्रवृति भी मिलेगी।

18. झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना

- 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरूआत की।
- इसका लाभ झारखंड के 20 लाख कार्ड धारियों को मिलेगा।
- इस योजना के तहत गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महिने 10 लीटर पेट्रोल पर 25रू प्रति लीटर की दर से 250रू सीधे उनके खाते मे भेजी जाएगी।

19. कोचिंग एण्ड एलाइड योजना

- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समूदाय के छात्र–छात्राओं को वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा।

20. पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना

- इस योजना की शुरूआत 20 दिसबंर 2021 को हुई
- इसके तहत पत्रकारों की 5 लाख तक की बीमा होगी।
- प्रिमीयम का 80 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी।

21.मसलिया–रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना

⇒ यह योजना संथाल परगना के दुमका जिले के 276 वैसे गांव जो ऊंचाई पर है , वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है।